

# e-Governance on way to UP villages

TIMES NEWS NETWORK

**Lucknow:** The National e-Governance Programme (NeGP) is taking an array of services to 70 per cent of India that lives in villages. The initiative is turning out to be a "novel experience for both the villagers and the service-providers."

This was stated on Friday by Major (retired) Ashutosh Srivastava, head of operations, SREI Sahaj e-Village Limited - the company that is developing a network of 8118 out of 17909 jan sewa kendras (JSKs) for UP.

As many as 13 JSKs are being set up in Lucknow. The work is on the verge of completion in Malhaur and Bakshi-ka-Talab areas.

JSKs will be a retail outlet of services offered through e-governance under the NeGP.

"Dilated pupils and strange expressions welcome me... They are finding it hard to believe," says the ex-Army officer.

The reaction is on account of a number of doubts.

Recalling his visit to a vil-

## Knowing the JSKs

**J**SK (Jan Sewa Kendra) will be a retail outlet of services offered through e-governance. Being developed under NeGP, launched in 2006, JSKs are technically known as Common Service Centres (CSCs).

The JSKs are the grass-root level units of a three-tier framework for implementation of the NeGP. Every five or six villages will have one JSK. JSKs will be controlled by a middle-level entity known as Service Centre Agency (SCA). TNN

lage in Gorakhpur, he said: "there was disbelief in the eyes of many people.

Some of them were trying to expedite the 'hidden agenda' behind the task, while others predicted an uncertain future for the project with reasons like availability of power and other essential services."

With such reactions, it re-

## Services through JSKs

TIMES NEWS NETWORK

**R**evenue, home, urban development, Panchayati Raj, health and family welfare, administrative reforms, food and civil supplies, social welfare, women and child welfare, disabled welfare, election commission, rural development, small-scale industries, primary, secondary, higher and technical education, power finance, planning and so on.

quires a lot of marketing skills to convince people.

For instance, people are told they would not have to run to tehsil office for getting a copy of their land records. When explained with the help of an SMS, they tend to get a rough idea.

"Thankfully, some people know there is something called a computer and help

us persuade the others," he said.

He informed that his company had been providing the same service in West Bengal and Bihar and the response had been overwhelming once the services started.

"Our franchisees are earning handsome amounts ranging from Rs 15,000 - Rs 50,000 a month," he said.

The JSK will be a retail outlet of services that are offered in a structured framework of IT services, rural entrepreneurship and market mechanisms.

It will provide e-governance services and critical information about governmental schemes and national programmes to help rural youth explore job opportunities within easy reach.

Besides, it will provide a platform for e-communication, avenues for e-marketing and e-shopping and opportunities for income enhancement. Since the basic framework originates from IT, facilities like printing, scanning, chatting, e-mailing, telemedicine and community television will also be made available.

# युनाइटेड भारत



ESTD 1951

संस्थापक : स्व. श्री शिवरामदास पु

RNI UP HIN/2001/2941 AD-2

वर्ष 1 अंक 202 मूल्य 2.00 रुप

लखनऊ, शनिवार, 14 जून

नगर संस्करण

सैक्स

## उ.प्र. के ग्रामीण अंचलों में जन सेवा केन्द्र

लखनऊ, १३ जून (बार्ता)। भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान (एनईजीपी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जनसेवा केन्द्र/कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) की स्थापना की जा रही है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना अर्थात् मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है।

सहज ई-विलेज लिमिटेड के हेड आफरेशन्स मेजर आशुतोष श्रीवास्तव ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आई.टी. क्रान्ति के बाद यह सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक व ग्रामीण उत्थान का एक बहुत बड़ा कदम है जिससे पारदर्शिता, सुलभता व सुचारुपन को बढ़ावा मिलेगा। इन जन सेवा केन्द्रों से इलेक्ट्रॉनिक डिलेवरी सिस्टम के माध्यम से सूचनाएं शासकीय सेवाएं व्यवसायिक सेवाएं शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार सहज जन सेवा केन्द्रों का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर करा रही है। राज्य को कुल सात जेन में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक जेन

के लिए सर्विस सेन्टर एजेंसी (एससीए) का चयन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद व मिर्जापुर मण्डलों के समस्त जनपदों के लिए श्रेयी सहज ई-विलेज लिमिटेड का चयन किया गया है जो सहज जन सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए ग्राम स्तर पर विलेज लेवल इन्टरप्रिन्योर (वीएलई) का चयन करेगी जिसको प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि श्रेयी सहज ई-विलेज लिमिटेड ई-गवर्नेन्स व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाली देश की अग्रणी कम्पनी है जो कि श्रेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स लिमिटेड की ग्रुप कम्पनी है। देश भर में बनने वाले एक लाख जन सेवा केन्द्रों में से तकरीबन २५ हजार जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य श्रेयी को मिला है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में १७९०९

जन सेवा केन्द्र बनने हैं जिसमें ८११८ सहज जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य श्रेयी ई-विलेज लिमिटेड कर रही है। लखनऊ जेन जिसमें लखनऊ गोरखपुर व बस्ती मण्डल शामिल हैं में ४४४९ तथा वाराणसी जेन जिसमें

इलाहाबाद व मिर्जापुर मण्डल शामिल हैं में ३६६९ जन सेवा केन्द्र स्थापित होने जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक सहज जन सेवा केन्द्र ०६ सेन्सेस विलेज के क्लस्टर पर स्थापित किया जायेगा।

इन सहज जन सेवा केन्द्रों का संचालन विलेज लेवल इन्टरप्रिन्योर (वीएलई) के द्वारा फ्रेंचाइजी आधार पर किया जायेगा जो गांव के पढ़े लिखे व कम्प्यूटर साक्षर लोग होंगे अथवा स्वयं सेवी संस्थायें होंगी। इनका चयन श्रेयी सहज ई-विलेज लिमिटेड के द्वारा योग्यता और अर्हता के आधार पर किया जायेगा। सहज जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को

सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ही स्थान पर प्रदान करना है और ई.गवर्नेन्स, ई.एजुकेशन, टेलीमेडिसिन आदि सेवाओं को बढ़ावा देना है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि सहज जन सेवा केन्द्रों की स्थापना से ग्रामीण जनता को दफ्तरों में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी जिससे उनका समय तो बचेगा ही साथ ही सरकारी सेवाएं उनके अपने ही गांव में प्राप्त हो जायेंगी। इनमें राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की जानकारी, फार्म, निर्वाचन सम्बन्धी सेवाएं, बिलों के भुगतान की सुविधायें, पंजीकरण सेवायें, रोजगार केन्द्र आदि सुविधायें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सहज जन सेवा केन्द्र पर कृषि व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इन केन्द्रों पर व्यवसायिक सेवायें जैसे बीमा, फोटोग्राफी, टाइपिंग, आन लाइन शापिंग, ई.मेल, पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाएं, बाहर से पैसा मंगाना या भेजना, टिकट बुकिंग आदि सेवायें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सलाह सम्बन्धी सेवायें भी दी जायेंगी।

सामाजिक व  
राष्ट्रीय उत्थान का  
बहुत बड़ा कदम

(अविभूति फेंड ईंट मूंदें मुटु प्रभ से भुजा तब ला गद औ बत पेंश अब



# e-governance goes rural

AS PART of the National e-Governance Plan (NeGP) of the Government of India, common service centres (CSCs) are being set up in rural areas across the country.

In UP, CSCs are being set up on a public-private-partnership (PPP) model. Of the 17,909 CSCs to be set up here, a private company, Shreyi Sahaj E-Village Ltd will set up 8,118 CSCs in Gorakhpur, Basti, Lucknow, Varanasi, Allahabad and Mirzapur divisions. Maj Ashutosh Srivastava, head (operations), UP said that the CSCs to be managed by them would be run by village-

level entrepreneurs. They would get the franchisee to manage them.

Srivastava said his company would choose village-level entrepreneurs on the basis of their academic efficiency and computer literacy. He said Sahaj CSCs would help create awareness and spread the concept of e-governance, e-education, tele-medicine facilities etc. "Rural people would not have to run from pillar to post to get their grievances redressed for our CSCs will provide them one-stop solution to all their needs," he said.

**HTC, Lucknow**